Estd. 1926

BCCI BULLETIN

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

Vol. XXXXV | 24th December 2014 | No. 19

भागलपुर में उद्योग लगाने की अपार संभावनाएँ

सेमिनार की मुख्य बातें

- हवाई जहाज के लैडिंग चार्ज को माफ करने के लिए सरकार से करेंगे बात
- मक्का, केला, चावल, फूड प्रोसेसिंग का भागलपुर में लग सकता है उद्योग।
- एकचारी में मक्का से अल्कोहल बनाने का लगेगा उद्योग – **रामचन्द्र सिंह**

सेमिनार को संबोधित करते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। मंच पर आसीन बाँयें से क्रमशः भागलपुर के मेयर श्री दीपक भुवानिया, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, इस्टर्न बिहार चैम्बर के महामंत्री श्री जगदीश चन्द्र मिश्रा, अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र कुमार सराफ एवं बिहार चैम्बर के महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पटना के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि भागलपुर में उद्योग लगाने की अपार संभावनाएं हैं। यहां के व्यापारियों को उद्योग लगाने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार की इस संबंध में अच्छी नीतियां हैं। उद्योग लगाने में चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर स्तर पर मदद करेगा। वह 13 दिसम्बर 2014 को **'भागलपुर में उद्योग की संभावना'** पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। श्री अग्रवाल ने कहा कि बिहार में व्यापार से जुड़ी सभी कमेटियों में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व है। यहां आने के बाद लगा कि उद्योग लगाने के संबंध में जानकारी का अभाव है। सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच रही है। पांच जनवरी को उद्योग विभाग की बैठक भागलपुर में होने वाली है। उस बैठक में उद्योग मंत्री, विभाग के प्रधान सचिव व अन्य अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में शामिल होकर उद्यमी जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन को लेकर पोशानी हो रही है लेकिन उसका भी समाधान हो जाएगा। उद्योग लगाने के लिए सरकार चार तरह की सब्सिडी दे रही है। उद्यमियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। उद्यमी अदालत प्रत्येक महीना के अंत में लगती है। वहां अपनी समस्याओं को रख सकते हैं।

उद्यमी पंचायत भी उद्यमियों के लिए लाभदायक है। संसद में 14 एक्ट को खत्म कर एक एक्ट बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लागू होने से छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि बिहार में 80 लाख टन चावल उत्पादन की क्षमता है। यहां भी छोटे-छोटे चावल मिल हैं लेकिन पंजाब की तरह बड़ा चावल मिल

सेमिनार में उपस्थित चैम्बर एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिगण।

सेमिनार में वक्ताओं की समस्याओं एवं सुझावों को नोट करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर चैम्बर के महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा तथा दाँयीं ओर इस्टर्न बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र कुमार सराफ, महामंत्री श्री जगदीश चन्द्र मिश्रा एवं डी०आई०सी०, भागलपुर के श्री रामचन्द्र सिंह।

सेमिनार में मंचासीन बाँयें से बिहार चैम्बर के कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, डी०आई०सी० भागलपुर के महाप्रबंधक श्री रामचन्द्र सिंह, इस्टर्न बिहार चैम्बर के महामंत्री श्री जगदीश चन्द्र मिश्रा, अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र कुमार सराफ, बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा, उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं भागलपुर की पूर्व महापौर डॉ० वीणा यादव।

लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागलपुर को रेशमी शहर के नाम से जाना जाता है। सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पटना के महासचिव ए० के० पी० सिन्हा ने कहा कि 2005 के बाद बिहार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बिहार में उद्योग लगाने के लिए अच्छा माहौल बना है। वक्ताओं ने कहा कि भागलपुर में मक्का, चावल , केला, गन्ना, आम, लीची आदि का उत्पादन अधिक होता है। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक रामचन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार उद्योग लगाने वालों को हरसंभव मदद देने को तैयार है। यहां हर तरह के उद्योग लगाये जा सकते हैं। एकचारी में 218 करोड़ की लागत से 15 एकड़ जमीन में उद्योग लगाया जा रहा है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। अतिथियों का स्वागत करते हुए इस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव जगदीश चन्द्र मिश्र ने कहा कि भागलपुर में उद्यमियों को छोटा-छोटा उद्योग लगाना चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस्टर्न बिहार चैम्बर के अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार सर्राफ ने कहा कि सरकार आधारभूत संरचना को बढावा देगी।

सेमिनार को संबोधित करते बिहार चैम्बर के महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा तथा मंचासीन भागलपुर के महापौर श्री दीपक भुवानिया एवं बिहार चैम्बर के कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

मंच संचालन इस्टर्न बिहार चैम्बर के उपाध्यक्ष अशोक भिवानीवाला ने किया। सेमिनार को मेयर दीपक भुवानिया, पूर्व मेयर डॉ. वीणा यादव के अलावा चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष रामगोपाल पोद्दार, मुकुटधारी अग्रवाल, गुजरात के व्यवसायी कल्पेश, नीरज कुमार, कहलगांव चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कमल कुमार टेकरीवाल, मुकेश कुमार जैन, प्रदीप झुनझुनवाला, बनवारी लाल खेतान, अभय वर्मन, नरेश अग्रवाल, शंकर लाल जैन आदि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष एस० के० पटवारी, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन, कार्यकारिणी सदस्य अशोक कुमार आदि उपस्थित थे।

राज्य में विधि व्यवस्था बेहतर : 'हिन्दुस्तान' से विशेष बातचीत में पी. के. अग्रवाल ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के बेहतर माहौल है। विधि-व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। जदयू-भाजपा गठबंधन से भाजपा के हटने के बाद विधि-व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई। लेकिन विधि-व्यवस्था को लेकर विश्वास में कभी आई है। जदयू के साथ राजद के गठबंधन पर अग्रवाल ने कहा कि किसी भी पार्टी के गठबंधन से उद्योग पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार स्थायी होनी चाहिए। विकास नीति अच्छी होनी चाहिए।

गुजरात से भागलपुर की जमीन दस गुनी महंगी : गुजरात के उद्योगपति कल्पेश बी० शाह भागलपुर में उद्योग लगाना चाहते है। इसके लिए कहलगांव क्षेत्र में 25 एकड़ जमीन देखी है। 20-25 करोड़ की लागत से वहां मक्के से तेल का उत्पादन और सोलर पावर प्लांट से बिजली उत्पादन से संबंधित उद्योग लगाने की तैयारी में जुटे हैं। इस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सेमिनार में पहुंचे शाह ने कहा कि यहाँ की जमीन गुजरात से दस गुनी महंगी है। सरकार को उद्योग लगाने के लिए

बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल को प्रतीक चिह्न भेंट करते इस्टर्न बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र कुमार सराफ। साथ में महामंत्री इस्टर्न बिहार चैम्बर के महामंत्री श्री जगदीश चन्द्र मिश्रा।

मदद करनी होगी। सरकार मदद नहीं करेगी तो उद्योग नहीं लगा सकते। दूसरी बार भागलपुर पहुँचे शाह ने कहा कि जो उद्योग लगाना चाहते है उसमें कहलगांव के गौतम मिश्रा पार्टनर है। दोनों का उद्योग मध्यप्रदेश में भी चल रहा है।

लालफीताशाही से नहीं लगे उद्योग : दिनांक 13 दिसम्बर 2014 को बिहार चैम्बर कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज पटना और इस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में 'भागलपुर में उद्योग की संभवनाओं पर सेमिनार आयोजित किया गया था। लेकिन अधिकांश वक्ता अफसरों की लाल फीताशाही पर बरसे। व्यापारियों का कहना था कि प्रशासनिक उपेक्षा के चलते भागलपुर में उद्योग नहीं लग रहा है।

व्यापारियों ने कहा कि जमीन का घोर अभाव है। सरकार की गलत नीतियों के चलते जमीन की कीमत काफी बढ़ गई है। दुर्भाग्य की बात है कि बियाडा में जो फैक्टरी लगाई गई आधारभूत संरचना की कभी के चलते बंद होने के कगार पर है। सिल्क उद्योग चरमरा गया है। सिल्क यार्ड और टेक्सटाइल्स पार्क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिहार का सबसे सुन्दर और सक्षम शहर होने के बाद भी भागलपुर में उद्योग नहीं लगना दुर्भाग्य की बात है। भागलपुर को पर्यटन के किसी सर्किट से जोड़ना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि यहाँ उद्योग लगाने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए। बियाडा में मनमानी बरती जा रही है। सब्सिडी नहीं मिलता है। पटना से भागलपुर आने में सात-आठ घटे लग जाता है। सात साल से हवाई सेवा शुरू होने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सब्सिडी की गलत नीतियों के चलते छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं। एक जमाने में भागलपुर उद्योग का हब हुआ करता था। पांच उद्योग बंद हो चुके है। उद्योग लगाने की संभावनाएं हैं लेकिन लोगों में हताशा है। अफसरशाही का नजरिया बदलना होगा। यहां अपहरण, रंगदारी और नक्सल का उद्योग चल रहा है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल के स्वागत में भागलपुर में लगा कहलगाँव चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं भागलपुर कैमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन का तोरण द्वार।

सेमिनार में मंचासीन बाँयें से भागलपुर के महापौर श्री दीपक भुवानिया, बिहार चैम्बर के कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, डी०आई०सी० भागलपुर के महाप्रबंधक श्री रामचन्द्र सिंह, इस्टर्न बिहार चैम्बर के महामंत्री श्री जगदीश चन्द्र मिश्रा, इस्टर्न बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र कुमार सराफ, बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा एवं उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी।

सेमिनार में बोले अतिथि

उद्योग लगने पर ही बड़ा मुनाफा मिल सकता है – मेयर : मेयर दीपक भुवनिया ने कहा कि किसी चुनौती से घबड़ाना नहीं चाहिए। उद्योग लगाने पर ही बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ उद्योग लगाने की जरूरत है। उद्योग नहीं लगने का मुख्य कारण जागरूकता की कमी है।

उद्योग लगाने के लिए आगे आयें – डॉ. वीणा : पूर्व मेयर डॉ. वीणा यादव ने कहा कि भागलपुर में केला, मक्का, सरसो तेल, गन्ना, आम आदि से संबंधित उद्योग लग सकता है। सेमिनार से व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। भागलपुर में उद्योग लगाने के लिए लोगों को आगे आना होगा।

चावल मिल जरूरी – रवि साह : रवि साह ने कहा कि धान का छिलका बाहर चला जाता है। उसे भेजने में ट्रांसपोर्टिंग खर्च अधिक लगता है। उसका उद्योग लगाया जा सकता है। एनटीपीसी के राख से सीमेंट और ईट बनाया जा सकता। पर्यटन से संबंधित उद्योग लगाने की जरूरत है।

सिल्क सिटी जाम सिटी बन गया – संजय : डॉ. संजय कुमार ने कहा कि सिल्क सिटी जाम सिटी बन गया है। प्रशासन के नाकारात्मक भाव के चलते उद्योग नहीं लग रहे हैं। यहाँ उद्योग लग सकते है। यहाँ कोकीन का उत्पादन नहीं हो रहा है। विदेशी धागा महंगा हो गया है।

बांका में उद्योग लगाने में मदद करें – तिवारी : बाँका चैम्बर के अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी ने कहा कि भागलपुर से बांका जाने में तीन से चार घंटे लग रहे हैं। अमरपुर और बांका में चावल और गुड का मिल था। दोनों की हालत खराब है। बांका में बड़े उद्योग लगाने की जरूरत है।

उद्योग की संभावना – बनवारी लाल खेतान : बनवारी लाल खेतान ने कहा कि भागलपुर में उद्योग लगाने की बहुत सभावनाएं है। इसके लिए एक-एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। धान की अच्छी फसल होती है। चावल का मिल लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी कई उद्योग लग सकते हैं।

जमीन के लिए उद्यमी को दौड़ना पड़ता है – मुकुटधारी : चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष मुकुटधारी अग्रवाल ने कहा कि भागलपुर में पहले के उद्योग बंद हो गये हैं। औद्योगिक नीति का पालन नहीं होता है। जमीन की कीमत अधिक है। व्यापारियों में हताशा है। जमीन और बिजली के लिए उद्यमियों को दौड़ना पड़ता है।

उद्योग लगाने की जरूरत – नीरज कुमार : डिजिटल प्रो के नीरज कुमार ने कहा कि व्यापारी उद्योग की स्थापना पर जोर देना चाहते हैं। लेकिन स्थापित नहीं कर पाते हैं। न आगे बढ़ने की हिम्मत कर पाते हैं और न ही पीछे मुड़ना चाहते हैं। यहाँ उद्योग लगाने के लिए सुविधाओं का अभाव है।

छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं – रामरतन चूड़ीवाला : रामरतन चूड़ीवाला ने कहा कि छोटे-छोटे कारखाना बंद हो रहे हैं। सब्सिडी की गलत नीति के चलते उद्योग प्रभावित हो रहा है। चावल मिल की स्थापना हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भागलपुर की कई मिलें बंद हो चुकी हैं।

भागलपुर उत्तराखंड बन सकता है – अभय वर्मन : अभय वर्मन ने कहा कि भागलपुर में उद्योग लगाने की सारी साभवनाएं है। पर्यटन के मामले में भागलपुर उत्तराखंड बन सकता है। यहाँ काफी मात्रा में मक्का की खेती होती है। बुनकर उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए। यहाँ डीआरएम कार्यालय खुलना चाहिए।

बियाडा मनमानी करता है – जैन : मुकेश कुमार जैन ने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए। बियाडा में मनमानी की जाती है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है। सब्सिडी नहीं दिया जाता है। काम कराने के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ना है। यहाँ तेल मिल सकता है।

यातायात व्यवस्था ठीक नहीं – कमल : कमल मोहन ठाकुर ने कहा कि भागलपुर में यातायात व्यवस्था ठीक नहीं है। पटना से भागलपुर आने में सात से आठ घंटे लग जाते हैं। उद्योग लगाने के लिए यहाँ के लोग सक्षम है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सात साल में हवाई सेवा शुरू नहीं की गई।

भागलपुर में उद्योग लगाना चाहता हूँ – शंकरलाल : शंकरलाल जैन ने कहा कि संसाधन की कमी के चलते उन्होने हरियाणा और राजस्थान में उद्योग लगाया है। वह भागलुपर में उद्योग लगाना चाहते हैं। उद्योग लगाने की बहुत संभावनाएं हैं लेकिन इसके लिए आधारभूत संरचना की जरूरत है। सड़क जरूरी है।

आम और लीची का उद्योग बन सकता है – प्रदीप : प्रदीप झुनझुनवाला ने कहा कि आम, लीची और केला से संबंधित उद्योग यहां लगना चाहिए। लीची से बीयर बन सकता है। आम से सॉस बनाने का उद्योग लग सकता है। आम से पापड़ बनाया जा सकता है। केला के थम से रेशम बन सकता है।

पर्यटन की आपार संभावना – पोद्दार : चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष रामगोपाल पोद्दार ने कहा कि यहां पर्यटन के क्षेत्र में सूचना केन्द्र अभी तक नहीं बना। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना है। सरकार की गलत नीति के चलते जमीन की कीमत अधिक हो गई है। टेक्सटाइल्स पार्क की योजना का बुरा हाल है।

छोटे उद्योग लग सकते हैं – अंसारी : इबरार अंसारी ने कहा कि छोटे उद्योग के लिए अधिक पूंजी की जरूरत नहीं होती है। छोटे उद्योग लगाये जा सकते हैं। छोटे उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए। भागलपुर के जरदालू आम का बहुत नाम है। इसका उद्योग लग सकता है। बिना छोटे उद्योग के बढ़ावा के विकास नहीं हो सकता है।

लाल फीताशाही के चलते उद्योग नहीं – अग्रवाल : साक्षी इण्डस्ट्रीज बियाडा के नरेश अग्रवाल ने कहा कि लाल फीताशाही के चलते उद्योग नहीं लग रहे है। बिजली सुधार के लिए 100 बार पत्र भेजा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रदूषण बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है। इससे पीड़ा होती है। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार से ही उद्योग लग सकता है।

केला-लीची का उद्योग लग सकता है – संजय कुमार : संजय कुमार ने कहा कि यहा की जमीन उपजाऊ है। कृषि आधारित उद्योग लगाया जा सकता है। केला, लीची, फूल, लेमनग्रास आधारित उद्योग लग सकता है। यहाँ पर्याप्त जल संसाधन है। मछली उत्पादन हो सकता है। पर्यटन का अच्छा केन्द्र बन सकता है। पटना के बाद भागलपुर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा हब है। **(साभार : हिन्दुस्तान, भागलपुर 14.12.2014)**

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के एमडी के साथ बैठक

बैठक को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर एसबीबीजे के प्रबंध निदेशक श्री ज्योति घोष एवं डिप्टी जीएम श्री ए० पांडा। दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा एवं कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्ध निदेशक, श्री ज्योति घोष के साथ बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने बताया कि श्री घोष मार्च 1980 में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़कर कई पदों को सुशोभित करते हुए आज स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्ध निदेशक के पद पर पहुँचे हैं। उन्होंने सूबे में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की और अधिक शाखाएं एवं एटीएम खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में एजुकेशनल लोन के मामले में भी इस बैंक का परफॉरमेंस बेहतर है। राज्य में सीडी रेशियो भी अन्य कॉमर्शियल बैंकों की तुलना में बहुत ज्यादा है। यहाँ सभी कॉमर्शियल बैंकों को मिलाकर 39.14 प्रतिशत रहा है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का सीडी रेशियो अकेले 85.74 प्रतिशत है। उन्होंने प्रबन्ध निदेशक से बिहार में उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा ऋण जिससे रोजगार के अवसर का सृजन होगा साथ ही शिक्षा ऋण भी ज्यादा से ज्यादा देने का अनुरोध किया।

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्ध निदेशक श्री ज्योति घोष ने खुद को पटना का मूल निवासी बताते हुए कहा कि शिक्षा ऋण के मामले में बैंक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। होम लोन के मामलों में भी आवेदन का निष्पादन बहुत अच्छा रहा है । बैंक शीघ्र ही अपनी शाखाओं की संख्या बढ़ाएगा और आने वाले वित्तीय वर्ष में इसे कम से कम 26 तक करने का लक्ष्य है। मौके पर बैंक के डिप्टी जीएम अच्युतानन्द पांडा ने कहा कि बैंक समस्तीपुर में टर्म लोन में बेहतरीन काम कर रहा है। कई फूड प्रोसेसिंग सेंटर को लोन दिया गया है। बैंक 13 दिसम्बर, 2014 को पटना के पीसी कॉलोनी में नई शाखा खोलेगा।

इस अवसर पर चैम्बर के श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष, श्री शशि मोहन, उपाध्यक्ष और श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष, श्री ए० के० पी० सिन्हा सहित चैम्बर सदस्य एवं मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे ।

Discussion with Labour Bureau Officials, Govt. of India on "Labour Reforms"

(R to L) Mr. J. A. Khan, Asst. Director, Labour Bureau, Shri P. K. Agrawal, President, Shri Subhash Kumar Patwari, Vice President, Shri Shashi Mohan, Vice President, Shri Mukesh Kumar Jain, Hony. Treasurer & Dr. B. B. Verma, Chairman, Labour Sub Committee.

Mr. J.A. Khan, Asstt.Director and Dr. Davendra Singh, Asstt. Director, Labour Bureau, Ministry of Labour, Government of India, Simla & Kanpur, visited Bihar Chamber of Commerce & Industries on 9th December, 2014 to discuss the Model Blank Proformae and Checks for

Collection of labour statistics for factories / establishments. The meeting was attended by the members of BCCI which generated interesting discussion on important "Forms" prescribed under the Labour Laws including Factories Act and Industrial Dispute Act.

The President of the Chamber, Shri P. K. Agrawal and Chairman, Labour Sub-Committee, BCCI, Dr. B. B. Verma were of the opinion that the existing labour laws were outdated and counter-productive in the context of present market economy, which required immediate reforms. The Government of India would be taking up the issues of "Labour Reforms" most likely in the Winter Session of Parliament. Therefore, the discussion must centrearound various aspects of "Labour Reforms" including drastic reduction in the number of existing "Forms" as well as other amendments in Labour Laws in order to boost the economy.

सिस्टम से पहले खुद को सुधारें

दैनिक जागरण कार्यालय सभागार में स्मार्ट सिटिजन-स्मार्ट सिटी अभियान के तहत शपथ लेते चैम्बर के पदाधिकारी एवं सदस्यगण।

सिर्फ सस्कार व सिस्टम को कोसने से काम नहीं बनेगा। जरूरत पहले खुद में सुधार लाने की है। राजधानी के व्यापार, उद्योग जगत से जुड़े प्रबुद्ध लोगों की ऐसी मान्यता है। वे 17 दिसम्बर 2014 को दैनिक जागरण कार्यालय में स्मार्ट सिटिजन-स्मार्ट सिटी अभियान के तहत राजधानी की ट्रेफिक व्यवस्था पर चर्चा करने जुटे थे। सभी ने इस मुहिम को सराहा तथा इसमें सकारात्मक योगदान देने की शपथ भी ली।

"अगर स्मार्ट सिटिजन, स्मार्ट सिटी मुहिम से युवा जुड़े तो बदलाव अवश्य होगा। नियमों का पालन सभी को करना चाहिए।"

–पी .के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

"अगर स्व. दशरथ मांझी अकेले पहाड़ खोद कर रास्ता बना सकते हैं तो हम भी अपने स्तर से प्रयास कर बदलाव ला सकते हैं।"

– **शशि मोहन,** वाइस प्रेसिडेंट, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

"दैनिक जागरण ने बेहतर अभियान की शुरुआत की है। ट्रैफिक नियम को बोझ नहीं समझना चाहिए।" **–नवीन कुमार मोटानी,** चेयरमेन, वैट सब कमेटी, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

"राजधानी में लोगों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी तक नहीं दी जाती है। नियमों को तोड़ना शान नहीं शर्म है।"

–सुरेश प्रकाश गुप्ता, पूर्व उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

"नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोगों को स्मार्ट सिटिजन बनाने को प्रेरित करें। अगर हम कानून नहीं मानते तो स्मार्ट नहीं है।"

–सावल राम ड्रोलिया, सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

"अगर छोटे बच्चे इस मुहिम के तहत ऑटो रिक्शा चालकों व अन्य लोगों से ट्रैफिक नियम का पालन करने का अनुरोध करें तो इसका प्रभाव दिखेगा।"

–उदयन सिंह, समाजसेवी व फिल्म मेकर।

"दैनिक जागरण को मुहिम की शुरुआत के लिए धन्यवाद। ट्रैफिक नियमों का पालन किसी दबाव में नहीं बल्कि कर्त्तव्य मान कर करें।"

–एन० के० ठाकुर, पूर्व महामंत्री, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

"गलत दिशा में गाड़ी चलाना, हेलमेट नहीं पहनना, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की आदत में खुद सुधार लाना होगा।"

–विशाल टेकरीवाल, सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

मंथन का अमृत

• जब 'वन मैन आर्मी के नाम से विख्यात दशरथ मांझी पहाड़ काट सकते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं • नियम तोड़ने वालों को आर्थिक दंड तो मिले ही, उन्हें दो घंटे बिठाकर भी रखा जाए • ट्रैफिक नियम का पालन के लिए मन में एक बार दृढ़ संकल्प तो लें। दूसरों को भी जागरूक करें • ट्रैफिक स्लो दिखे या सड़क जाम हो तो गाड़ी पहले ही पार्क कर लें। बेवजह जाम न बढ़ाएं।

"अगर हम नियम जानते भी हैं तो उसका पालन नहीं करते। हम दंड से बचने के लिए कभी कभार ट्रैफिक नियमों का पालन कर लेते हैं।"

–सुबोध जैन, पूर्व कोषाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

"ट्रैफिक सेंस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गली, नुक्कड़ व चौराहों पर सभाएं, गोष्ठी आयोजित करनी होगी।"

–मुकेश जैन, कोषाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

"थोड़ी सी समझदारी शहर को ट्रैफिक की समस्या से बचा सकती है। जाम में फंसने से अच्छा है कि जगह देखकर अपनी गाड़ी पार्क कर दें।"

–नन्हे कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स।

"ट्रैफिक के नियम पहले हमें अपनी सोच में स्थापित करनी होगी। हमें यह समझना चाहिए कि लोगों के सहयोग से जब बेंगलुरु में ट्रैफिक स्मुथ हो सकता है तो फिर अपने शहर में क्यों नहीं? क्या बिना डंडे के भय के हम कुछ सही नहीं कर सकते?" **–राज कुमार सराफ,** सदस्य, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज।

(साभार : दैनिक जागरण, 18.12.2014)

शाहकुंड में भी लग सकते हैं उद्योग : पी. के. अग्रवाल

प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए यहाँ पर उद्योग लगाने की अपार संभावना है। उक्त बातें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, पटना के अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने शाहकुंड दौरे के दौरान पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि हमारा पैतृक गाँव पंचरुखी है। उन्होंने कहा कि छह दशक में शाहकुंड इलाके का काफी विकास हुआ हैं। यहाँ सैकड़ों दुकानें खुल चुकी हैं। उन्होंने बताया कि शाहकुंड अमरपुर मुख्य मार्ग पर बांका मीमा से सटे तथा सजौर बाज़ार में इण्डस्ट्री लगाने के लिए कई लोग जमीन देने के लिए इच्छुक हैं जिससे यहाँ के परिवेश को बदला जा

सके एवं लोगों को रोजगार भी मिल सके। उन्होंने उद्योग लगाने की पहल को लेकर जिला उद्योग महाप्रंबधक ई. रामचंद्र से बात की। उन्होंने बताया कि सजौर में जल्द ही इण्डस्ट्री लगाई जाएगी और इसके लिए जमीन भी उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है। इसके बाद शाहकुंड में इण्डस्टी लगाने के लिए जमीन खोजी जाएगी। पत्रकारों से वार्ता करने के बाद वे मुंगेर आइटीसी के लिए रवाना हो गए।

(साभार : दैनिक जागरण (भागलपुर) 15.12.2014)

प्रशासन की नाक के नीचे गंदगी, फिर भी बेपरवाह

शहर गंदा है। शहर की सड़कें और गलियां भी गंदी हैं। यह बात इतना बताने के लिए काफी है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर रूप देने वाली व्यवस्था काम नहीं कर रही है। लेकिन, स्थिति तब और भी विवादास्पद हो जाती है जब प्रशासन की नाक के नीचे कचरा रहे और इसके बाद भी प्रशासन मौन रहे। इससे पूरे शहर का क्या आलम होगा, समझा जा सकता है।

दिनांक 14.12.2014 को दैनिक जागरण स्वच्छ पटना–स्वच्छ भारत अभियान की टीम ने गांधी मैदान के निकट जिला प्रशासन ऑफिस के पीछे बने विकास भवन के आसपास का जायजा लिया। ये वही जगह है जहां स्टेट बैंक का रीजनल हेडक्वॉर्टर, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा दूसरे कई सरकारी कार्यालय है। इसके साथ ही एक क्लब और थोक सब्जी मंडी भी यहीं पर है। हमने अपने अभियान के क्रम में महसूस किया कि बड़े–बड़े सरकारी दफ्तर होने और क्लब होने के बाद भी यहां सफाई पर किसी का जोर नहीं है। पूरी व्यवस्था मानो भगवान भरोसे हो। यहां कार्यालयों से निकला कूड़ा तो जो गंदगी फैलाता ही है, पूरी सड़क और इलाके को सबसे ज्यादा गंदा कोई कर रहा है तो वे हैं सब्जी के थोक विक्रेता। विकास भवन से थोड़ा आगे कचरे का बोझ इतना बताने के लिए काफी है कि यहां से कचरा कभी–कभी ही उठता है।

पास में ही कुछ झुग्गी–झोपड़ियां भी बना ली गई हैं। यहां के लोग भी सड़क पर ही गंदगी फैलाते हैं। जिन्हें रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन भी इन पर हाथ डालने से परहेज करता है। यहाँ लोगों ने वर्षों से कब्जा जमाए रखा है। कई बार उन्हें हटाने की कोशिश की गई, पर सफलता नहीं मिली। कलेक्ट्रेट में हर रोज आने वाले हजारों लोग यहाँ इसी कचरे के पास से होकर गुजरने को मजबूर हैं। यदि प्रशासन चाहे तो एक दिन में पूरे इलाके की सफाई हो सकती है, लेकिन जहां चाह ही नहीं होगी वहां अंतत: राह निकलेगी भी तो कैसे। (साभार : दैनिक जागरण, 16.12.2014)

थाना और जिला स्तर पर भी नागारिक परिषद का गठन

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिनांक 13.12.2014 को बिहार राज्य नागरिक परिषद की पहली बैठक में निर्देश दिया कि थाना एवं जिला स्तर पर भी नागरिक परिषद का गठन किया जाए। राज्य नागरिक परिषद के कार्यों को गति देने का भी फैसला लिया गया। इस बाबत राज्य नागरिक परिषद के सदस्यों से सुझाव भी लिए गए। इस बैठक में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह भी उपस्थित थे।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.12.2014)

कंपनी संशोधन बिल पारित

पोंजी योजनाओं से धन हड़पनेवालों को मिलेगी कड़ी सजा

देश में व्यापार एवं कारोबार संबंधी माहौल को अधिक सुगम और सुचारु बनाने तथा पोंजी योजनाओं के जरिये जनता के धन को हड़पनेवालों को कड़ी सजा देने के प्रावधान करनेवाले 'कंपनी संशोधन विधेयक 2014' को लोकसभा ने 17.12.2014 को पारित कर दिया।

कंपनी अधिनियम में किये गये 14 महत्वपूर्ण संशोधनों में जनता से धन एकत्र कर अवैध कारोबार चलानेवालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यह संशोधन सारधा घोटाले की पृष्ठभूमि में लाया गया है जिसने छोटे निवेशकों से लाखों करोड़ों रुपये हड़पे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि संशोधनों के जरिये विधेयक में से आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) जैसे दमनकारी प्रावधानों को हटाना था, जिनके चलते कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोपियों के लिए जमानत तक हासिल करना बेहद मुश्किल था। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश विधेयक में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की ओर से वर्ष 2013 में पारित नये कंपनी कानून के विभिन्न प्रावधानों में 14 बदलाव किये गये हैं।

निवेश बढ़ेगा, व्यापार करना होगा आसान : जेटली ने कहा, 'व्यापार को कड़ा बनाना मकसद नहीं है, बल्कि व्यापार को सुगम बनाना तथा निवेश आकर्षित करना विधेयक का मकसद है।' उन्होंने कहा कि पिछले विधेयक में चार महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं जिनमें कारोबार को सरल बनाना, मसौदे की गलतियों को सुधारना, विधेयक के कुछ दमनकारी प्रावधानों को हटाते हुए कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करना शमिल है। सरकार द्वारा औद्योगिक चेंबरों, संस्थाओं, विधि विशेषज्ञों और मंत्रालयों एवं विभागों समेत विभिन्न पक्षों से प्राप्त ज्ञापनों में कारोबार करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को अभिव्यक्त किया गया है। विधेयक में अवैध तरीके से धन जमा करने की गतिविधि, फर्जी योजनाओं के जरिये लोगों को ठगने जैसी गतिविधियों में दंड का प्रावधान किया गया है। (साभार : प्रभात खबर, 18.12.2014)

'BIHAR SECOND EMERGING ECONOMY'

ENCOURAGING The framework for assessing the states is based on the micro-economic diamond model laid down by acclaimed management guru Michael E. Porter

Uttar Pradesh tops the list of emerging economies ranking within India, followed closely by Bihar in the State category, said The India State Competitiveness Report 2014 of The Institute for Competitiveness an international think tank in a report released on 17.12.2014.

Goa, which "shows strengths in the context of strategy and rivalry for businesses that operate in the region and also has strong supporting and related industries, tops in the city state Category of a competitiveness report.

Goa replaced Delhi " due the credit availability to businesses that have operated in the city -state", the report said.

The report categorizes the states under seven heads-city states, innovation driven economies, transition economies, investment driven economies, changeover economies, emerging economies and north-eastern economies. (Detail : Hindustan Time, 18.12.2014)

STATE GIVES ASSENT TO GST

Petroleum products would be out of the ambit of GST as per a consensus evolved by the states and central government, which is all set to implement uniform tax collection on goods and services across the country from April, 2016.

Sources said, state finance minister Bijendra prasad Yadav in his last meeting with Union finance minister Arun Jaitley had conveyed the state's view that the Centre should compensate states like Bihar in terms of losses to be incurred following discontinuation of entry tax at that state borders on vehicles. Other states also participated in the meeting on December 11.

"Bihar has already given its assent to GST. There were certain issues, which have been sorted out" said a senior finance officer, seeking anonymity.

Principal finace commissioner Rameshwar Singh said the meeting had resolved that petroleum would be out of the ambit of GST and collections through VAT imposed on petroleum products would go to state coffers for the time being.

VAT on petroleum products generate big revenue for states, especially those with low development, like Bihar.

Another highlight of the meeting was the Centre's go ahead to the proposal that states can impose additional taxes in liue of entry tax to overcome losses following implementation of GST.

State like Maharashtra and other developed states would suffer huge revenue losses following discontinuation of entry tax and they have voiced demands for compensation of the losses for four to five years from the Centre.

Sources said, the Union finance ministry has assured the states that their concerns over revenue losses would be taken care of and also agreed to the demand for proper amendment in the constitutional provisions so that there is a legal binding.

"A firm IT network would be gives shape in the next one year before the roll out of GST," officials said.

Bihar's retired chief secretary Navin Kumar is the head of the special purpose vehicle, which is steering the IT network for GST across the country. (Source : Hindustan Time, 18.12.2014)

अस्पताल खोलने पर करों में मिलेगी छूट

प्रस्ताव **बिहार हेल्थकेयर इंवेस्टमेंट पॉलिसी तैयार, लीज पर सरकारी जमीन, 35% तक सब्सिडी**

राज्य में अस्पताल खोलेंगे तो 5 सालों तक करों में रियायत व लीज पर सरकारी जमीन मिलेगी। निवेश राशि पर 35% तक की सब्सिडी भी। लोन पर 7 वर्षों तक 5% वार्षिक ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। उद्यमियों द्वारा खुद भू-अर्जन पर भी सहूलियत मिलेगी। ये प्रावधान राज्य की प्रस्तावित हेल्थकेयर इंवेस्टमेंट पॉलिसी में किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पॉलिसी तैयार कर ली है। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। मौजूदा मल्टी व सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल अगर आधारभूत संरचना में 50% का विस्तार करेंगे तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।

सूपर स्पेशिएलिटी अस्पताल को सिंगल विंडो एप्रुवल : पॉलिसी का उद्देश्य सुपर स्पेशिएलिटी और मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल खोलना है। ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। परियोजनाओं को सिंगल विंडो एप्रुवल दी जाएगी। पॉलिसी में किसी भी तरह का संशोधन राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद ही कर सकेगा। सरकार द्वारा जमीन देने पर उसके मूल्य को प्रोजेक्ट कॉस्ट में शमिल नहीं माना जाएगा।

मल्टी स्पेशिएलिटी : न्यूनतम 200 बेड के अस्पताल खोलने होंगे। नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्र में 3 और उसके बाहर 5 एकड़ में खुलेंगे। कम से कम 100 करोड़ का निवेश जरूरी। यहां जिला अस्पतालों के समान हर तरह के बेसिक इलाज की सुविधाएं देनी होगी।

सुपर स्पेशिएलिटी : विशिष्ट रोगों के इलाज वाले कम से कम 100 बेड के अस्पताल। ये नगर निगम और नगरपलिका क्षेत्र में 2 और बाहर 3 एकड़ में खुलेंगे। इस अस्पताल में कम से कम 80 करोड़ का निवेश करना होगा। इनमें सरकार द्वारा तय की जाने वाली सुविधाएं देनी होंगी।

सूक्ष्म उद्योग लगाने वालों को सूद पर भी 2% मदद : अब सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए कर्ज पर सूद में भी सरकार मदद देगी। सामान्य जाति के उद्यमी को सूद की राशि का एक और एससी-एसटी, ओबीसी व महिला उद्यमी को दो प्रतिशत राशि मिलेगी। यह घोषणा उद्योग मंत्री डॉ. भीम सिंह ने 17.12.2014 को बिहार राज्य मिलर्स एसोसिएशन के सम्मेलन में की। उन्होंने कहा-सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए 25 प्रतिशत अनुदान दे रही है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 18.12.2014)**

अगर इन कंपनियों में पैसा लगाया, तो डूब जायेंगे

रहिए सतर्क **झांसा देकर पैसा ठगनेवाली कंपनियों की सूची जारी, जितनी जल्दी हो सके जमा राशि को निकाल लेने की सलाह**

देश के कई राज्यों में कुछ नॉन बैंकिंग कंपनियां ऐसी हैं, जो सिर्फ 'पोंजी स्कीम' (वैसी वित्तीय योजनाएं जिन्हें सिर्फ ठगी के मकसद से एनवीसी चलाती हैं) के जरिये लोगों से पैसो ठगने का काम करती हैं। इन कंपनियों को कलेक्टिव इनवेस्टमेंट स्कीम की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी कंपनियों के वित्तीय मामलों के लेन-देन की मॉनीटरिंग सेबी करता है। सेबी ने सिर्फ सीआइस के तहत काम करनेवाली 51 एनबीसी को ब्लैकलिस्टेड किया है। इन कंपनियों में लोगों को पैसा जमा नहीं करने या जमा पैसे को जल्द निकाल लेने की सलाह दी है। कई कंपनियां कई जिलों में काम कर रही हैं। इससे पहले भी 72 फर्जी एनबीसी कंपनियों की सूची जारी की गयी थी, लेकिन इसमें सीआइएस शेयर या डिवेंचर्स और अन्य सभी तरह से ठगी करने वाली कंपनियों का नाम था। इस बार की सूची में सिर्फ सीआइएम वाली कंपनियों का नाम है। हाल में 'पीएसीएल' नामक एनबीसी के 10 जिलों में कार्यालयों पर छापेमारी कर सील किया गया था। कंपनी पर करीब 29 हजार करोड़ रुपये घोटाले का आरोप है।

रहे सतर्क, करे एफआइआर : ये कंपनियां अपनी मौजूदगी की सूचना संबंधित जिला कार्यालय में नहीं देती हैं। इससे इनकी जानकारी सरकार को तभी होती है, जब ये फरार हो जाती हैं। इसलिए इन कंपनियों के प्रति लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर किसी कंपनी में किसी ने निवेश कर रखा है, तो इसके खिलाफ एफआइआर दर्ज करायें।

सेबी की वेबसाइट पर कंपनियों की सूची देख सकते हैं या सेबी के टॉल फ्री नंबर 18002667575/18002227575 पर भी जानकारी ले सकते हैं।

फर्जी कंपनियों की सूची : • सन प्लांट एग्रो लिमिटेड • एनजीएचआइ डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड • एमपीएस ग्रीनरी डेवलपर्स लिमिटेड • नाइसर ग्रीन फॉरेस्ट लिमिटेड • मैत्रेय सर्विस प्राइवेट लिमिटेड • ओसियंस कोन्नोआयर्स ऑफ आर्ट लिमिटेड • श्रद्धा रियलिटी इंडिया लिमिटेड • केन इन्फ्राटेक लिमिटेड • अल्केमिस्ट इन्फ्रा रियलिटी लिमिटेड • सुमंगल इंडस्ट्रींज लिमिटेड • एचबीएन डेयरीज एंड एलाइड लिमिटेड • साई प्रसाद फूड लिमिटेड • साई प्रसाद प्रोपर्टीज लिमिटेड • मैत्रेय प्लॉटर्स एंड स्ट्रक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड • एमवीएल लिमिटेड • समरुद्धा जीवन फूड्स इंडिया लिमिटेड • सर्वहित हाउसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड • ओरियंट रिसॉर्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड • किम इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लिमिटेड • ग्रीन रे इंटरनेशनल लिमिटेड • रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब लिमिटेड • इकोग्रीन रीयलस्टेट (इंडिया) लिमिटेड • पीयर्स एलाइड कॉरपोरेशन लिमिटेड • ग्रीम बड एग्रो फॉर्म लिमिटेड • केबीसीएल इंडिया लिमिटेड • ऐडेल लैंडमार्क लिमिटेड (इरा लैंडमार्क्स लि) • जेएसआर डेयरीज लिमिटेड • निखारा भारथ कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड • हलधर रियलिटी एंड इंटरप्राइजेज लिमिटेड • रोज वैली रीयल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड • बीटेल लाइवस्टोक्स एंड फॉमर्स लिमिटेड • रैमेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड • रीमैक रीयल्टी इंडिया लिमिटेड • सनसाइन एग्रो ग्लोबल लिमिटेड (सनसाइन फॅारेस्टी प्राइवेट लिमिटेड) • एली मल्टी ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड • साई प्रसाद कॉरपोरेशन लिमिटेड • नाइसर ग्रीन हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड • धनोल्टी डेवलपर्स लिमिटेड • जेएसवी डेवसपर्स इंडिया लिमिटेड • एचएनसी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड शेयर्स इंडिया • शुभम क्रोती फूड्स प्राइवेट लिमिटेड • विश्व रीयल एस्टेट एंड इन्फास्ट्रक्चर इंडिया • आइएचआइ डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड • पीएसीएल, स्टेप अप मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड • एसपीएनजे लैंड प्रोजेक्ट्स एंड डेक्लपर्स जीएन डेयरीज लिमिटेड, शीन एगो एंड प्लांटेशन लिमिटेड • गरिमा रीयल एस्टेट एड एलाइड लिमिटेड • राघव कैपिटल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड • श्री साई स्पेस क्रिएशन लिमिटेड।

(साभार : प्रभात खबर, 16.12.2014)

डेयरी विकास के लिए 'स्व लागत योजना' शुरु

राज्य सरकार ने डेयरी विकास योजना में कई बदलाव किए हैं। पशुपालन विभाग ने पिछड़े क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देने की रणनीति बनायी है। योजनाओं को लागू करने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनेगी। डेयरी विकास के लिए 'स्व लागत योजना' शुरू की गई है। योजना के तहत बिना बैंक लोन के ही लाभुक सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं।

गव्य विकास योजना में इस वित्तीय वर्ष में 66 करोड़ खर्च करने की योजना है। सभी जिलों को पशु खरीदने व राशि खर्च करने का लक्ष्य दिया गया है। जो गव्य विकास पदाधिकारी टारगेट पूरा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़े जिलों में 35 से 40 हजार गाय व छोटे जिलों में 15 से 20 हजार गाय खरीदवाने का लक्ष्य दिया गया है। योजना के तहत लाभुक को स्वयं पशु शेड बनवाना होगा और गाय खरीदनी होगी। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बैद्यनाथ सहनी ने कहा कि लाभुकों के लिए स्व लागत योजना शुरू की गई है, ताकि डेयरी विकास योजना का लाभ गरीबों तक पहुंच सके। **(साभार : हिन्दुस्तान, 18.12.2014)**

बिजली उपभोक्ताओं की ऑनलाइन निगरानी शुरु

फतुहा के बाद अब हाजीपुर के बिजली उपभोक्ताओं की भी ऑनलाइन निगरानी शुरू हो गई। 17.12.2014 को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने रिस्ट्रक्चर्ड एक्सेलेरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म्स प्रोग्राम (आरएपीडीआरपी) के तहत हाजीपुर में चल रहे काम का उद्घाटन (गो लाइव) किया।

फतुहा का हो चुका है उद्घाटन : हाजीपुर के किस उपभोक्ता को किस ट्रांसफॉर्मर व पोल से कितनी बिजली दी जा रही है, निगरानी की जा सकेगी। सूबे के 71 शहरों में आईटी आधारित बिजली सेवा पर काम हो रहा है। इसमें उत्तर बिहार के 33 तो दक्षिण बिहार के 38 शहर शमिल हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना के फतुहा में सबसे पहले काम शुरू हुआ था। बीते 15 नवम्बर को केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था। दो सालों में सभी 71 शहरों में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में ऊर्जा सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक प्रत्यय अमृत, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय कुमार सिंह, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की प्रबंध निदेशक पलका साहनी व नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालामुरूगन डी भी मौजूद थे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.12.2014)

आज स्थापना दिवस | बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के 88 साल पूरे

विकास में निभा रहा अहम भूमिका

गौरवशाली इतिहास की गवाही देता बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स का भवन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में ले चुके है हिस्सा (फाइल फोटो)

21 दिसंबर, 1926 को हुई थी स्थापना

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज रविवार को अपनी स्थापना के 88 साल पूरा करेगा। इसकी स्थापना 21 दिसम्बर, 1926 को हुई थी। 22 दिसम्बर को यह 89 वें साल में प्रवेश कर जायेगा। 88 वर्षों के दौरान चैम्बर ने कई उतार-चढ़ाव देखे। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चैम्बर में आ चुके हैं। 12 जून, 2010 को उन्होंने चैम्बर परिसर में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भाग लिया था। 1926 से ही बिहार के विकास में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तत्पर है। यह सरकार की पॉलिसी के क्रियान्वयन में हमेशा से सहयोग देता रहा है।

यह सरकार और व्यापारी समुदाय के बीच एक पुल का काम करता है, जो निजी क्षेत्र को सही दिशा में ले जाती है। मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना की स्थापना में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है 0.792 एकड़ में फैले चैम्बर परिसर की स्थापना अंटा घाट से हुई। आधुनिकता और समय के साथ इसमें बदलाव होते रहे।

2002 में जारी हुआ डाक टिकट

देश में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहला संगठन है, जिस पर 2002 में डाक टिकट जारी किया था यह अपने आप में कीर्तिमान है। चैम्बर समय-समय पर लोगों की मदद के लिए भी आगे रहा है।

महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण

चैम्बर न केवल राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की सेवा में तत्पर है, बल्कि अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है। चैम्बर फरवरी 2014 से महिलाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण का कार्य कर रहा है। अब तक लगभग 400 महिलाओं ने मुख्यतः 12 तरह की सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उपलब्धियों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, जनप्रतिनिधि, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैप्टन ऑफ इण्डस्ट्री एण्ड कॉमर्स द्वारा सराहा गया। सबसे पहले 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद सिल्वर जुबली के मोके पर आये थे। इसके बाद राष्ट्रपति वीवी गिरि, आरके वेंकटरमन, फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दौरा किया था। इन सबों ने चैम्बर के कार्यों को सराहा था।

पूर्व राष्ट्रपति ने बताया सहयोगी

पूर्व राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने चैम्बर के प्लेटिनम जुबली 2003 का उद्घाटन किया था। इसके बाद वे मार्च 2006 में भी आये थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिहार के इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सक्रिय सहयोगी है। उसी साल के मई में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने दौरा किया तथा उन्होंने भी सदस्यों को संबोधित किया।

विशिष्ट स्थान है चैम्बर का

88 साल की यह संस्था हो गयी। इसने समाज के बदलाव के विभिन्न आयामों को देखा। कोई भी बुरा प्रभाव संस्था को न प्रभावित कर सका और न डिगा सका। उन पुरानी संस्थाओं में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एक विशिष्ट स्थान रखता है। अपने कार्य से हमेशा समाज और राज्य के उत्थान, चाहे सामान्य स्थिति में या असामान्य स्थिति में, राज्य के हित में हमेशा कार्यरत रहा। कहा जा सकता है कि राज्य में वैट एक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2006 एवं फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2011 को बनाने में सरकार का भरपूर सहयोग चैम्बर ने किया।

इतिहास के आईने में

- बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज का गठन बिहार और ओडिशा सरकार द्वारा किया गया था। इसके बाद एक मई। 1925 को एजुकेशन विभाग के भीतर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गठन के पीछे एस दास -कटक, दीवान बहादुर आरके जालान-पटना, राय बहादुर वंशीधर ढंढानिया-भागलपुर, बीएफ मदन, राधा कृष्ण आर. सी. पंडित का अहम योगदान रहा।
- 19 जनवरी, 1926 को बिहार और ओडिशा सरकार ने इस कमेटी के गठन के लिए स्वीकृति ही।
- 23 मार्च, 1926 को बिहार और ओड़िशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से रजिस्ट्रेशन किया गया।
- इसका विधिवत उद्घाटन 9 सितम्बर, 1926 को किया गया।
- 21 दिसम्बर, 1926 को बिहार व ओडिशा सरकार ने मान्यता प्रदान किया।
- 1937 में इसका नाम बिहार एण्ड ओडिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बदल कर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स किया गया। अभी इसका नाम बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बदल कर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज कर दिया गया है। इसको 28 जुलाई, 2012 में इजीएम से स्वीकृति मिली।

"उद्योगों के लिए जमीन कैसे उपलब्ध हो सके, इस पर बिहार चैम्बर ने काफी प्रयास किया। चैम्बर के सुझाव पर सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की पॉलिसी बनायी है। चैम्बर ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सिलाई मशीन भी प्रदान की।"

– पी० के० अग्रवाल, अध्यक्ष

(साभार : प्रभात खबर, 21.12.2014)

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org
Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296